



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

निर्यात में उछाल: वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी

अप्रैल-अगस्त 2024 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2025 में निर्यात में 5.19 प्रतिशत की वृद्धि,

व्यापार में बढ़ रहा विश्वास

मुख्य बातें

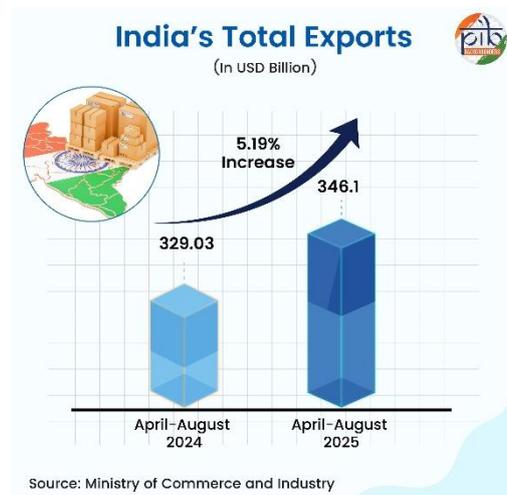
- भारतीय निर्यात ने अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में 4.77 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- अप्रैल-अगस्त 2024 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में निर्यात 5.19 प्रतिशत बढ़कर 346.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अप्रैल-अगस्त 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2.31 प्रतिशत तक बढ़ गया और सर्विस एक्सपोर्ट 8.65 प्रतिशत बढ़ गया।
- हांगकांग, चीन, अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, बेल्जियम, बांग्लादेश और ब्राजील को भारत का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2024 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2025 में बढ़ा है।

परिचय

भारतीय निर्यात की यात्रा वैश्विक एकीकरण के साथ नवाचार का परिणाम है। सिल्क रूट से लेकर उदारीकरण के बाद के उछाल तक, निर्यात में मसालों और वस्त्रों से लेकर प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग वस्तुओं तक विविधता आई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया का निर्यात 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का निर्यात वैश्विक विकास से आगे बढ़कर 7.1 प्रतिशत (2024) की दर से बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर देश की प्रगति का संकेत देता है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी 2015 में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 21.2 प्रतिशत हो गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था (विश्व बैंक) में निर्यात की बढ़ती प्रासंगिकता को

भी बताता है। भारत के व्यापार प्रदर्शन ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पांच महीनों में भी विकास की प्रवृत्ति जारी रखी।

- अप्रैल-अगस्त 2024 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2025 में कुल निर्यात (व्यापारिक और सेवा निर्यात संयुक्त) में 5.19 प्रतिशत की वृद्धि।
- अप्रैल-अगस्त 2025 के लिए कुल निर्यात मूल्य 346.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 में यह 329.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अप्रैल-अगस्त 2025 में व्यापारिक निर्यात का हिस्सा 53.09 प्रतिशत था।
- अप्रैल-अगस्त 2025 में सेवा निर्यात का हिस्सा 46.91 प्रतिशत रहा।
- अगस्त 2024 के मुकाबले अगस्त 2025 में निर्यात में 4.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।



इस विकास पथ को स्वीकार करते हुए, सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसमें से 34.61 प्रतिशत पहले पांच महीनों में ही हासिल कर लिया गया है।

सरकारी सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित, देश का निर्यात क्षेत्र नई संभावनाओं के शिखर पर खड़ा है, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर भारत की कहानी को नया आकार दे रहा है।

वस्तु निर्यात वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक

भारत का व्यापारिक निर्यात 2025 में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसने अप्रैल-अगस्त 2025 में 2.31 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की, जहां अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान 179.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में निर्यात 183.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

हालांकि पांच महीनों में से 19 प्रतिशत मर्चेडाइज एक्सपोर्ट केवल अगस्त 2025 में किया गया था,

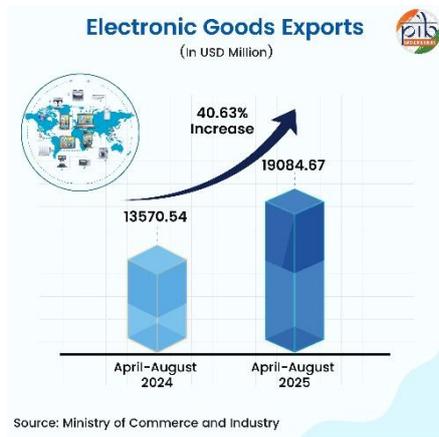


जिसमें पिछले वर्ष से 6.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

भारत का गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात अप्रैल-अगस्त 2025 में बढ़कर 146.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 136.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 7.76 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। यह श्रेणी इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और अन्य द्वारा संचालित भारत की निर्यात शक्ति को उजागर करती है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाय, अभ्रक और कोयला, कपड़ा आदि जैसी वस्तुओं ने पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की।

इलेक्ट्रॉनिक सामान



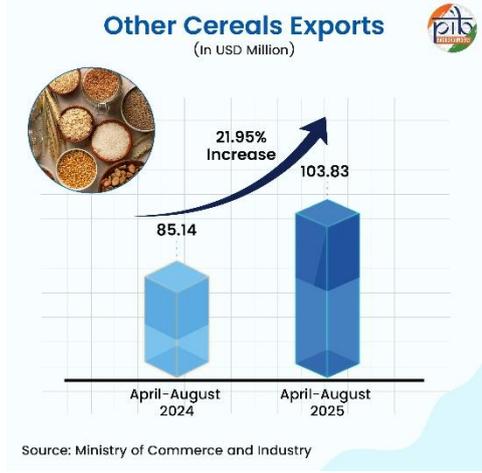
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं ने विकास की गति का नेतृत्व किया, निर्यात में 5.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो अप्रैल-अगस्त 2025 में पिछली इसी अवधि की तुलना में 40.63 प्रतिशत की वृद्धि है। कमोडिटी ने अगस्त 2025 में भी पिछले वर्ष की तुलना में 25.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 8 गुना वृद्धि हुई। मेक इन इंडिया और पीएलआई

योजनाओं द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नीदरलैंड और यूके सहित प्रमुख बाजारों के साथ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात बढ़ रहा है।

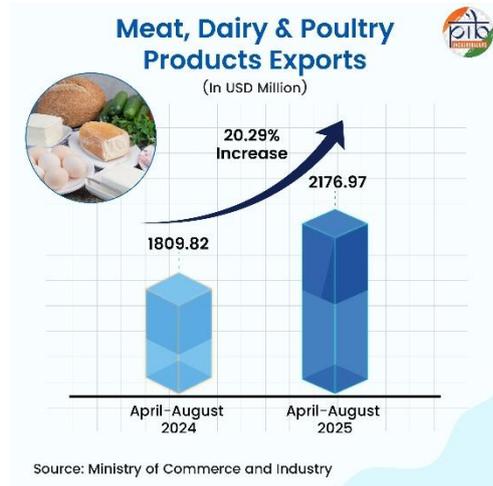
स्मार्टफोन प्रमुख विकास चालकों में से एक बना हुआ है। इस क्षेत्र में भारत एक शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदल रहा है। वित्त वर्ष 2026 के केवल पांच महीनों के भीतर स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक है।

अन्य अनाज

अप्रैल-अगस्त 2024 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में भारत के अन्य अनाजों के निर्यात में 21.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें राई, जौ, जई, फोनियो, क्विनोआ आदि शामिल हैं। इसमें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा शामिल नहीं हैं। अन्य अनाजों की वैश्विक मांग में वृद्धि के पीछे एक कारण पौष्टिक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक खाद्य उत्पादों के प्रति जागरूकता है। भारत की समृद्ध कृषि विरासत के साथ, ये अनाज कृषि विविधता को बढ़ाते हैं, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं और निर्यात के नए अवसर प्रदान करते हैं। शीर्ष निर्यात गंतव्य नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और भूटान हैं।



मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद

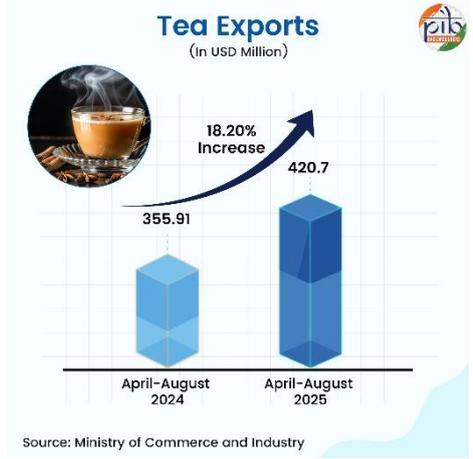


पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों में 20.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 के दौरान 17.69 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई। वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, मलेशिया और सऊदी अरब भारतीय मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के कुछ आयातक हैं।

निर्यात में वृद्धि को विभिन्न सरकारी पहलों द्वारा उत्प्रेरित किया गया है। उदाहरण के लिए, कृषि निर्यात नीति बाजार पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है और किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करती है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना (एपीडा) निर्यात बुनियादी ढांचे के विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास में व्यवसायों की सहायता करती है।

चाय

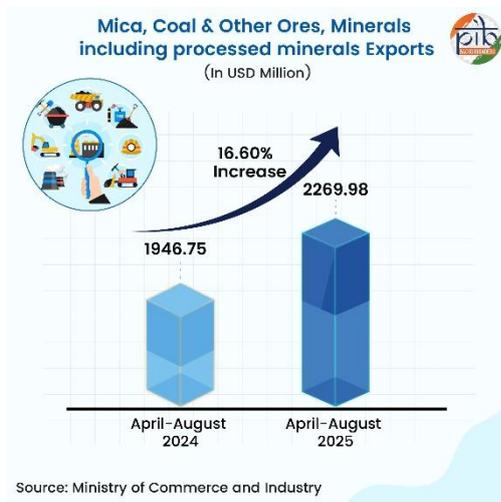
चाय ने निर्यात में वृद्धि दर्ज की और पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में 18.20 प्रतिशत अधिक हो गई। चाय निर्यात में भी अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में 20.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे समग्र चाय निर्यात वृद्धि में तेजी आई।



भारत ने वैश्विक चाय उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि चाय दुनिया के बेहतरीन चाय में शुमार हैं। काली चाय निर्यात में सबसे आगे है, जो 96 प्रतिशत शिपमेंट बनाती है, जबकि ग्रीन, हर्बल, मसाला और लेमन टी जैसी किस्में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को और बढ़ाती हैं।

भारत कई देशों को चाय का निर्यात करता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, इराक, अमेरिका, रूसी संघ और ईरान शीर्ष गंतव्यों के रूप में उभरे हैं।

अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिज



अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिज निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में 16.60 प्रतिशत बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में 24.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगस्त 2025 में भी कमोडिटी की बढ़ती मांग का अनुभव किया गया। कुछ शीर्ष देश जहां भारत प्रसंस्कृत खनिजों और उनके उप-उत्पादों का निर्यात करता है, वे चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ओमान और बांग्लादेश हैं।

अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं/क्षेत्र

अप्रैल-अगस्त 2024 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2025 में प्रतिशत बदलाव		
इंजीनियरिंग सामान	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधान
5.86 प्रतिशत ↑	7.30 प्रतिशत ↑	5.78 प्रतिशत ↑

भारत के पारंपरिक निर्यात मुख्य आधार इंजीनियरिंग वस्तुओं ने भी स्थिर लाभ दर्ज किया, जो अप्रैल-अगस्त 2024 में 46.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर से **अप्रैल-अगस्त 2025 में 5.86 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 49.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ब्रिटेन और सऊदी अरब के साथ अमेरिका प्रमुख गंतव्य बना रहा। औद्योगिक मशीनरी श्रेणी के तहत निर्यात किए जाने वाले प्रमुख सामान आईसी (आंतरिक दहन) इंजन और पुर्जे, डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, औद्योगिक मशीनरी जैसे बॉयलर, पार्ट्स, मोल्डिंग इंजेक्ट करने के लिए मशीनरी, वाल्व और एटीएम हैं। भारत सरकार ने इंजीनियरिंग के निर्यात को मजबूत बनाए रखने के लिए **जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई)** जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य निर्यातकों को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से राजस्व बढ़ाने में मदद करना है।

ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात अप्रैल-अगस्त 2024 में 11.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2025 में 12.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए, जो **वर्ष की तुलना में 0.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7.30 प्रतिशत) की वृद्धि है**। सस्ती जेनेरिक और विशेष दवाओं की आपूर्ति करने की भारत की क्षमता ने उन्नत और उभरते बाजारों से मांग को बनाए रखा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका शीर्ष खरीदारों के रूप में शामिल हैं। इस क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संवर्धन के लिए सरकार की पहल जो स्पष्ट रूप से विकास में योगदान देती हैं, उनमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए यूनिफॉर्म कोड (यूसीपीएमपी) 2024 और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 शामिल हैं।

कैलेंडर वर्ष 2024 में 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधान, श्रम केंद्रित क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देना जारी रखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में इसका निर्यात 5.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 6.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन के नेतृत्व में पारंपरिक बाजारों में मांग में तेजी बनी रही, जो वैश्विक परिधान आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की मजबूत उपस्थिति की पुष्टि करती है। घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर, टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ाकर और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत के ब्रांड को मजबूत करके इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से इस क्षेत्र के विकास में तेजी आ रही है।

भारत के रणनीतिक व्यापार संबंध: शीर्ष व्यापारिक निर्यात गंतव्य

भारत के रणनीतिक व्यापार संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक निर्यात का लगातार विस्तार हो रहा है। अप्रैल-अगस्त 2024 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में कई देशों को भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़ा है।



एक गेटवे के रूप में हांगकांग: 2024-25 में हांगकांग को भारत का व्यापारिक निर्यात 6.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये निर्यात भारत के विविध व्यापार पोर्टफोलियो को उजागर करते हैं, जिसमें रत्न और आभूषण जैसी लक्जरी वस्तुओं से लेकर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं।

अप्रैल-अगस्त 2025 में हांगकांग को व्यापारिक निर्यात 26.19 प्रतिशत बढ़कर 2.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हांगकांग, जिसे लंबे समय से "चीन के प्रवेश द्वार" के रूप में देखा जाता है, अब बढ़ते भारत-चीन आर्थिक संबंधों के बीच "भारत का प्रवेश द्वार" बनने की क्षमता रखता है। 2024 में हांगकांग के माध्यम से भारत और चीन के बीच पुनः निर्यात व्यापार 97.9 बिलियन हांगकांग डॉलर (12.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। यह वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका और इसके निर्यात क्षेत्रों की ताकत को दर्शाता है।

एशिया में पड़ोसी चीन के साथ व्यापार: चीन को भारत के व्यापारिक निर्यात में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 14.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें अप्रैल-अगस्त 2025 में साल-दर-साल 19.65 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक उत्पाद और लौह अयस्क और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

यह भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमताओं और चीन के विनिर्माण क्षेत्र के लिए कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का निर्यात: अगस्त 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का व्यापारिक निर्यात 6.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण और वस्त्र शामिल हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम अन्य देशों को भारत का व्यापारिक निर्यात			
भारत के निर्यात गंतव्य	जुलाई 2025 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	अगस्त 2025 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
संयुक्त राज्य अमेरिका	8012.45	6865.47	↓
संयुक्त अरब अमीरात	2984.66	3245.26	↑
नीदरलैंड	1668.92	1829.77	↑
ऑस्ट्रेलिया	495.65	554.67	↑
नेपाल	600.85	617.26	↑
दक्षिण अफ्रीका	611.28	654.58	↑
हांग कांग	548.15	584.70	↑

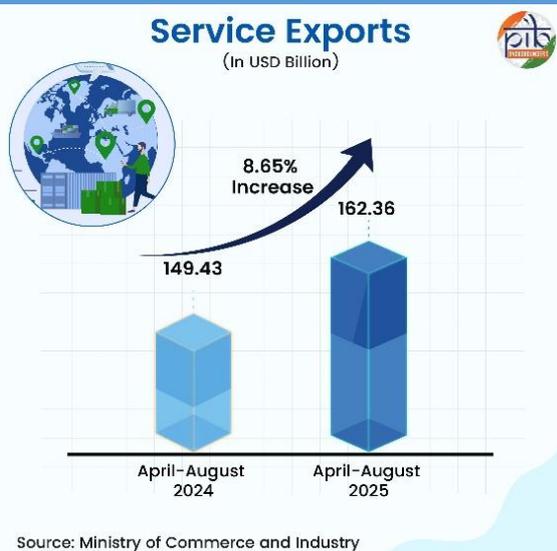
संयुक्त राज्य अमेरिका को लगातार निर्यात वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और एक गतिशील बाजार में उच्च मूल्य वाले उत्पादों को वितरित करने की क्षमता को दर्शाता है। यह भारतीय आयातों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की स्थिति में भारत की तैयारी को दर्शाता है। जुलाई 2025 से अगस्त 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात में कमी आई है और इसी अवधि में अन्य देशों के साथ निर्यात में वृद्धि हुई है। विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत उत्पाद की गुणवत्ता को उन्नत कर रहा है, वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठा रहा है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहा है और नए बाजारों का दोहन कर रहा है। बढ़ते निर्यात के साथ-साथ, देश अपने निर्यात स्थलों में विविधता ला रहा है, जिससे भारतीय उत्पादों के वैश्विक भविष्य को बढ़ावा मिल रहा है।

यूरोपीय देश जर्मनी के साथ व्यापार: वर्ष 2024-25 में जर्मनी को भारत का व्यापारिक निर्यात लगभग 10.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान कुल निर्यात का 40 प्रतिशत है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, भारतीय वस्त्र और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। अप्रैल-अगस्त 2025 में, जर्मनी को भारतीय व्यापारिक निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 11.73 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो

यूरोपीय देश के साथ बढ़ते व्यापार का संकेत देता है। जर्मनी को भारत का व्यापारिक निर्यात महत्वपूर्ण है क्योंकि वे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ के बाजार के लिए एक प्रमुख केंद्र के साथ व्यापार को गहरा करते हैं।

पूर्वी एशिया, कोरिया में भारत की उपस्थिति: भारत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाले व्यापार संबंधों के साथ कोरिया के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024-25 में, इंजीनियरिंग सामान (कोरिया को कुल निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक), पेट्रोलियम उत्पाद और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन ने कोरिया को 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया। **अप्रैल-अगस्त 2025 में, कोरिया को व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 9.69 प्रतिशत यानी 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई,** जो भारतीय उत्पादों पर कोरिया के उपभोक्ताओं के विश्वास को दर्शाता है। इन निर्यातों को **भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) द्वारा और अधिक समर्थन दिया गया है,** जिसने टैरिफ को कम किया है और भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच में सुधार किया है।

सेवा निर्यात: भारत के निर्यात वृद्धि का नया इंजन



आर्थिक समीक्षा 2024-25 में सेवा क्षेत्र को 'ओल्ड वॉर हॉर्स' के रूप में संदर्भित किया गया था, जो इसकी निरंतर ताकत और अर्थव्यवस्था को चलाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। **पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025 में 8.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ,** भारत के सेवा निर्यात ने लचीलेपन और विकास का प्रदर्शन जारी रखा, जिससे वैश्विक सेवा अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में देश की स्थिति मजबूत हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन और पेशेवर परामर्श जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित, सेवा क्षेत्र भारत की विदेशी मुद्रा आय में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। **अप्रैल-अगस्त 2025 में सेवा क्षेत्र का व्यापार अधिशेष 79.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।** इसके संबंध में, सेवा क्षेत्र में व्यापार अधिशेष के साथ समग्र व्यापार घाटे में गिरावट लाने में सेवा क्षेत्र का भी योगदान है। 2025 में भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि का श्रेय निरंतर विकास को बढ़ाने वाले कई प्रमुख कारकों को दिया जा सकता है:

प्रौद्योगिकी क्षेत्र: वित्त वर्ष 2024 में भारत का तकनीकी क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद का 7.3 प्रतिशत था। 2030 तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की समग्र अर्थव्यवस्था में लगभग पांचवें हिस्से में योगदान देने का अनुमान है। तकनीकी प्रगति और क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और फिनटेक सहित डिजिटल समाधानों को तेजी से अपनाने ने उच्च मूल्य वाली डिजिटल सेवाओं में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का विस्तार किया है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं भी इस क्षेत्र को समर्थन दे रही हैं।

जनसांख्यिकीय विभाजन: भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। देश के लगभग 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं जो अन्य देशों की तुलना में इसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को मजबूत करते हैं। एक युवा आबादी बेहतर उत्पादकता और बढ़ी हुई उपभोक्ता मांग की क्षमता के साथ एक बड़े कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान जनसांख्यिकीय विभाजन और कौशल भारत कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के साथ कौशल विकास पर भारत सरकार के ध्यान के साथ, सेवा क्षेत्र कुशल कार्यबल के साथ ईंधन भरता रहता है।

एफडीआई मानदंडों का उदारीकरण: भारत सरकार हमेशा नियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, बुनियादी ढांचे को विकसित करके, रसद को बेहतर बनाकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को बढ़ाकर कारोबारी माहौल में सुधार करके अधिक एफडीआई आकर्षित करने का प्रयास करती है। उदाहरणों में से एक यह है कि केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सेक्टरल कैप को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है, जो पूरे प्रीमियम को भारत में निवेश करती हैं।

इसी तरह, **भारत-यूके सीईटीए में, भारत ने यूके से व्यापक प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं।** डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में यूके की प्रतिबद्धताएं यूके के लगभग 200 बिलियन अमरीकी डालर के आयात में हिस्सेदारी का विस्तार करने के लिए आईटी और व्यावसायिक सेवाओं में निरंतर मजबूत विकास को सक्षम बनाएगी। देशों के साथ व्यापार सौदों और सेवा क्षेत्र में विकास के लिए नीतियों के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षेत्र के विकास का अध्ययन होता है।

भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

भारत की निर्यात संवर्धन योजनाएं बुनियादी ढांचे की अक्षमताओं को दूर करके, लागत कम करके, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर निर्यात प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी पहलों का एक व्यापक समूह है। इन पहलों का परिणाम यह है कि जून 2024 की तुलना में जून 2025 में आयातक देशों द्वारा भारतीय निर्यात किए गए उत्पादों की अस्वीकृति की दर में 12.5 प्रतिशत की कमी आई है।



भारत विदेश व्यापार नीति 2023 के माध्यम से विदेशी व्यापार और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, जो छूट, व्यापार करने में आसानी, सहयोग और नए बाजारों के लिए प्रोत्साहन का समर्थन करता है। इससे निर्यातकों को पुराने लंबित प्राधिकरणों को बंद करने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका भी मिलता है। आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को एम्बेडेड शुल्कों, करों और लेवी के लिए प्रतिपूर्ति करती है जो अन्यथा किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किए जाते हैं। इसने मार्च, 2025 तक लगभग 58,000 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

निर्यात हब के रूप में जिले जैसी पहल राज्यों और जिलों को व्यापार में सक्रिय खिलाड़ी बना रही है। निर्यात क्षमता वाले 734 जिलों की पहचान की गई है और 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार किया गया है। एसईजेड व्यापार का समर्थन करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 14.56 लाख करोड़ रुपये के रोजगारों, निवेश और निर्यात को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

भारत कई प्रमुख पहलों के माध्यम से अपने व्यापार और लॉजिस्टिक्स में सुधार कर रहा है। टीआईईएस (निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना) परीक्षण प्रयोगशालाओं, गोदामों और कार्गो सुविधाओं जैसे निर्यात-केंद्रित बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है। पीएम गतिशक्ति योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से परिवहन को तेज और हरित बना रही है। भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक्स रैंक 2018 में 44 से बढ़कर 2023 में 38 हो गई है। इस बीच, 2020 में शुरू की गई पीएलआई योजना 14 क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है, 1.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित कर रही है, उत्पादन

में 16.5 लाख करोड़ रुपये का सृजन कर रही है और मार्च 2025 तक 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर रही है।

भारत ने व्यापार करने में आसानी की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, जो 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर 2020 में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 2014 के बाद से 42,000 अनुपालनों को खत्म करने और 3700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे सुधार प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

डिजिटल उपकरण भी व्यापार को बदल रहे हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम अनुमोदन को सरल बनाता है, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म व्यापार प्रश्नों के समाधान और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यातकों का मार्गदर्शन करता है, ई-कॉमर्स निर्यात हब सीमा शुल्क, प्रमाणन, पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग जैसी एकीकृत सुविधाएं प्रदान करते हैं, छोटे शहरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ते हैं, और आइसगेट ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, आईपीआर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, सीमा शुल्क ईडीआई पर दस्तावेज़ ट्रेकिंग स्थिति, ऑनलाइन सत्यापन और अन्य को सुव्यवस्थित करता है। यह 24x7 हेल्पलाइन सुविधा है।

भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए नए कदम

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार

- 1 नवंबर, 2025 से सिस्टम-संचालित जोखिम जांच के आधार पर शून्य-रेटेड आपूर्ति के लिए 90 प्रतिशत अनंतिम रिफंड।
- निर्यात पर जीएसटी रिफंड के लिए मूल्य आधारित सीमा हटाई गई। इससे छोटे निर्यातकों को मदद मिलेगी क्योंकि वे अपने छोटे मूल्य की खेपों पर भी रिफंड का दावा कर सकते हैं।
- पेपर पैकेजिंग, कपड़ा, चमड़ा और लकड़ी पर जीएसटी 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम होती है, जिससे निर्यातक अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश कर सकते हैं। टर्कों और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, और पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे माल ढुलाई और रसद लागत कम होगी, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसके अलावा, खिलौनों और खेल के सामानों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके, सस्ते आयात का मुकाबला किया जा सके और बढ़ती वैश्विक मांग का दोहन किया जा सके।

- "मध्यस्थ सेवाओं" के लिए आपूर्ति का स्थान ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, ताकि ऐसी सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को निर्यात लाभ का दावा करने में मदद मिल सके।
- कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण में इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर में सुधार से कार्यशील पूंजी का दबाव कम होता है, रिफंड निर्भरता कम होती है और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलता है।
- जोखिम-आधारित आधार पर इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर (आईडीएस) दावों के लिए 90 प्रतिशत अनंतिम रिफंड।

निर्यात संवर्धन मिशन

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन का समन्वय वाणिज्य विभाग के साथ-साथ एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मिशन के तहत, एमएसएमई को समर्थन देने पर विशेष ध्यान देने के साथ, निर्यात ऋण पहुंच, सीमा पार व्यापार के लिए फैक्ट्रिंग और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के इरादे से 2,250 करोड़ रुपये की पहल का प्रस्ताव किया गया है।

नए व्यापार समझौते

व्यापार समझौते व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए देश (देशों) या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच समझौते हैं, हालांकि व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से आपसी बातचीत होती है। कुछ नए व्यापार समझौते जिन पर चर्चा की जा रही है या जारी है, वे हैं:

- भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)
- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
- भारत और ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
- भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
- भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

निष्कर्ष

माल और सेवाओं दोनों में फैला भारत का मजबूत निर्यात प्रदर्शन, वैश्विक बाजार में देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलेपन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, अन्य अनाज, चाय, डेयरी, अभ्रक उत्पादों जैसी शीर्ष प्रदर्शन वाली वस्तुओं में उल्लेखनीय वृद्धि, प्रमुख गंतव्य देशों को बढ़े हुए व्यापारिक निर्यात के साथ, भारत की निर्यात पहलों और योजनाओं की प्रभावशीलता को उजागर करती है। सरकार के नीतिगत हस्तक्षेपों ने निर्यातकों को विश्वास बढ़ाया है, नवाचार का समर्थन किया है, व्यापार के लिए बाजार को आसान बनाया है और बाजार के अवसरों का विस्तार किया है। भारतीय व्यापार मानकों के मजबूत होने के साथ ही निर्यात में वृद्धि आर्थिक विकास, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की प्रभावशाली स्थिति को और तेज करने के लिए तैयार है।

संदर्भ:

प्रेस सूचना ब्यूरो

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1868284>

<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025814608701.pdf>

<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=149107>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelD=154945&ModuleId=3>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155151&NotelD=155151&ModuleId=3>

वस्त्र मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156220>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2162261>

वित्त मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097911>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108360>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163555>

https://gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2025-09/press_release_press_information_bureau.pdf

नीति आयोग

<https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-12/Trade-Watch.pdf>

विश्व बैंक

<https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=IN>

<https://lpi.worldbank.org/international/global>

डीडी न्यूज़

<https://ddnews.gov.in/en/indias-exports-to-surpass-last-year-despite-tariffs-piyush-goyal/>

<https://ddnews.gov.in/en/pli-schemes-see-actual-investment-of-rs-1-76-lakh-crore-create-over-12-lakhs-jobs-minister/>

<https://ddnews.gov.in/en/indias-transformative-decade-landmark-reforms-drive-ease-of-doing-business/>

<https://ddnews.gov.in/en/india-oman-agree-to-speed-up-talks-on-signing-bilateral-economic-pact/>

ट्विटर

https://x.com/AshwiniVaishnav/status/1967496528135889375?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

संसद

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2737_MAtnjv.pdf?source=pqals

निर्यात डॉट जीओवी डॉट इन

https://niryat.gov.in/#?start_date=202404&end_date=202503&sort_table=export_achieved-sort-desc

आईबीईएफ

<https://www.ibef.org/exports/coffee-industry-in-india>

<https://www.ibef.org/exports/agriculture-and-food-industry-india>

<https://ibef.org/news/india-surpasses-china-in-smartphone-exports-to-united-states-us>

इन्वेस्ट इंडिया

<https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/5-key-factors-driving-indias-growth-tech-investment-destination>

न्यूज़ ऑन एआईआर

<https://www.newsonair.gov.in/new-delhi-hits-out-after-us-announces-additional-tariffs-asserts-india-will-take-all-necessary-actions-to-protect-national-interests/>

<https://www.newsonair.gov.in/india-achieves-significant-milestone-in-global-tea-industry-becomes-worlds-2nd-largest-exporter-of-tea-in-2024/>

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/GDP_PR_Q1_2025-26_29082025.pdf

विदेश मंत्रालय

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/website_brief_India-Hong_Kong_Bilateral_Relations_1_.pdf

<https://indbiz.gov.in/dashboard/#ranking>

केरल सरकार

<https://industry.kerala.gov.in/index.php/district-as-exports-hub>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2025/02/LS-Unstarred-No-234.pdf>

<https://sezindia.gov.in/sites/default/files/factsheet/FACT%20SHEET%20ON%20SEZs%20as%20o%20n%2030.06.2025.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156504>

<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specifidocs/documents/2025/sep/doc2025915637401.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101785>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1912572>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2131526>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1907322>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152518>

<http://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2108151>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736>

<https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/top-12-indian-sezs-global-investors>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163475>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2166088>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160190>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127826>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736>

<https://indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=0&id=0.31.24100.24109>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168168>

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147394>

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112193>

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

<https://www.nsws.gov.in/>

सीआईआई

https://www.cii.in/International_ResearchPDF/India%20Peru%20Report%202025.pdf

पीके/केसी/केके/एचबी